

उपासना स्थल अधिनियम, 1991

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सांसद इकरा चौधरी ने [उपासना स्थल \(वशिष प्रावधान\) अधिनियम, 1991](#) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है।

मुख्य बटु

- गौरतलब है कयिह अधिनियम कसिी भी पूजा/उपासना स्थल की स्थतिको उसी अवस्था में रोक देता/बनाए रखता है, जैसा कविह 15 अगस्त, 1947 को थी।
- [उपासना स्थल \(वशिष उपबंध\) अधिनियम, 1991:](#)
 - यह पूजा स्थलों ([राम जनमभूमि-बाबरी मसजदि विवाद](#) के मामले को छोड़कर, जसिका मामला पहले से ही अदालत में था) की "धार्मिक प्रकृति" को वर्ष 1947 की स्थतिके अनुरूप बनाए रखने का प्रयास करता है।
- **उद्देश्य:**
 - इस अधिनियम का उद्देश्य उपासना स्थलों की धार्मिक स्थतिको संरक्षित रखना तथा वभिन्नि [धार्मिक संप्रदायों](#) के बीच या एक ही संप्रदाय के भीतर धर्मांतरण को रोकना है।
 - इस अधिनियम की धारा 3 के तहत पूजा स्थल या यहाँ तक कउसके खंड को एक अलग धार्मिक संप्रदाय या एक ही धार्मिक संप्रदाय के अलग वर्ग के पूजा स्थल में परिवर्तित करने को प्रतर्बिधति कयिा गया है।
 - इस अधिनियम की धारा 4(2) में कहा गया है कपूजा स्थल की प्रकृतिको परिवर्तित करने से संबंधित सभी मुकदमे, अपील या अन्य कार्रवाईयाँ (जो 15 अगस्त, 1947 को लंबित थीं) इस अधिनियम के लागू होने के बाद समाप्त हो जाएंगी और ऐसे मामलों पर कोई नई कार्रवाई नहीं की जा सकती।
 - यह अधिनियम सरकार के लिये भी एक सकारात्मक दायित्व निर्धारित करता है कविह हर पूजा स्थल के धार्मिक चरतिर/प्रकृतिको उसी प्रकार बनाए रखे जैसा कविह स्वतंत्रता के समय था।
- **अपवाद:**
 - अयोध्या का विवादित स्थल (राम जन्मभूमि-बाबरी मसजदि) को इस अधिनियम से छूट दी गई थी। इसी छूट के कारण इस कानून के लागू होने के बाद भी अयोध्या मामले में मुकदमा आगे बढ़ सका।
- **इसके अलावा इस अधिनियम में कुछ अन्य मामलों को भी छूट दी गई:**
 - कोई भी पूजा स्थल जो ['प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल](#) अवशेष अधिनियम, 1958' के तहत शामिल प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक या एक पुरातात्विक स्थल है।
 - ऐसे मुकदमे जनिका नसितारण हो चुका है या जनि पर अंतिम फैसला दयिा जा चुका है।
- **दंड:**
 - इस अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ अधिकतम तीन वर्ष के कारावास के दंड का प्रावधान है।
- **सर्वोच्च न्यायालय का मत:**
 - वर्ष 2019 में अयोध्या मामले के फैसले में [सर्वोच्च न्यायालय](#) की संवैधानिक पीठ ने इस कानून का उल्लेख करते हुए कहा कयिह संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को प्रकट करता है और इसकी प्रतगिगमिता को सख्ती से प्रतर्बिधति करता है।
- **याचिका में दयि गए तरक:**
 - याचिका में इस अधिनियम को इस आधार पर चुनौती दी गई है कयिह अधिनियम [धर्मनिरपेक्षता](#) का उल्लंघन करता है।
 - इस याचिका में यह तरक दयिा गया है क'15 अगस्त, 1947 की कट-ऑफ तथिा "मनमाना, तरकहीन और पूरवव्यापी" है तथा [यहूदियों, जैन, बौद्धों और सिखों](#) को अपने "पूजा स्थलों" पर पुनः दावा करने के लिये अदालत जाने से रोकती है, जनि पर "कट्टरपंथी बर्बर आक्रमणकारयिों" द्वारा "आक्रमण" कर "अतकिरण" कर लयिा गया था।
 - याचिका में यह तरक दयिा गया है ककिेंद्र के पास "तीर्थस्थल" या "कब्रसितान" पर कानून बनाने की कोई शकृतिनीही है, जो राज्य सूची के तहत आते हैं।
 - हालाँकि सरकार के अनुसार, वह इस कानून को लागू करने के लिये [संघ सूची](#) की प्रवषिट'97 के तहत अपनी [अवशषिट शकृति](#) का उपयोग कर सकती है।
 - संघ सूची की प्रवषिट'97 केंद्र को उन वषियों पर कानून बनाने के लिये अवशषिट शकृतिप्रदान करती है जनिहें (जनि वषियों को) तीनों में से

कसिी भी सूची में शामिल नहीं कयिा गया है ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/places-of-worship-act,-1991-2>

